ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/324168054

□□□□□□□□□□□ : □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

Research · January 2017

CITATIONS
0

READS
2

1 author:

Bhagawati Paraksh Sharma
Pacific University India
268 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Bhagawati Paraksh Sharma on 03 April 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

आवरण कथा

विमुद्रीकरणः

निवेश व रोजगार वृद्धि की आवश्यकता

सरकार द्वारा नवंबर 9, 2016 से 1000 व 500 रूपये के बड़े मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के अनेक प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहे हैं। इस नोटबंदी का सबसे बड़ा लाभ जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को निष्प्राण करने एवं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पूर्वोत्तर में माओवादी, नक्सली व अन्य प्रकार की वामपंथी हिंसा व आतंकवाद को समाप्त करने में बड़ी सफलता मिली है।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक 132 करोड़ जनसंख्या वाला और पहला सर्वाधिक युवा जनसंख्या अर्थात् विश्व के 20 प्रतिशत युवाओं से युक्त देश है। देश में प्रतिमाह दस लाख व वर्ष भर में 1.2 करोड़ नवीन युवा रोजगार पाने वालों की प्रतीक्षा सूची में जुड़ जाते हैं। इसलिये देश की आर्थिक नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता इस निरंतर बढ़ रही युवा शक्ति को रोजगार सुलभ कराने की होनी चाहिये। आज से 2300 वर्ष पूर्व चाणक्य ने भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में लोगों को जीवनवृत्ति अर्थात् लाभपूर्ण रोजगार दिलाने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया है। आज देश के 13.96 लाख विद्यालयों में 31.5 करोड़ व 788 विश्वविद्यालयों सहित 45000 महाविद्यालयों में 3.3 करोड़ छात्र अध्ययनरत हैं। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की यह संख्या अमेरिका व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कनाडा की जनसंख्या के तुल्य है। अतएवं देश की आर्थिक नीतियों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन हेतु कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य में सतत् निवेश प्रवाह बनाये रखना पहली प्राथमिकता होनी आवश्यक है। लेकिन देश में, विगत कुछ वर्षों में निवेश में आ रहे गतिरोध, निर्यातों में 21 माह से चल रहे गिरावट के दौर, बैंकों की बढ़ रही अनिष्पादनीय आस्तियों के चलते, विमुद्रीकरण के बाद भू–संपदा व निर्माण में गतिरोधवश सीमेंट, अन्य निर्माण सामग्री एवं संबंधित उद्योग वर्गों सहित कुछ रोजगार क्षेत्र भी अंशतः प्रभावित हुये हैं।

देश में कालेधन, अवैध रूप से संचित राशि व नकली मुद्रा पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा नवंबर 9, 2016 से 1000 व 500 रूपये के बड़े मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के अनेक प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहे हैं। इस नोटबंदी का सबसे बड़ा लाभ जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को निष्प्राण करने एवं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पूर्वोत्तर में माओवादी, नक्सली व अन्य प्रकार की वामपंथी हिंसा व आतंकवाद को समाप्त करने में बड़ी सफलता

मिली है। अवैध और नकली मुद्रा के माध्यम से प्रेरित की जा रही हिंसात्मक गतिविधियों पर एक बार पूर्णविराम लग जाने से यह भी स्पष्ट हो गया कि इन सारी गतिविधियों के पीछे कोई वैचारिक मुद्दा नहीं था और ये विशुद्ध रूप से राष्ट्रविरोधी शक्तियों द्वारा केवल अवैध धन व नकली मुद्रा से चलायी जा रही है। विमुद्रीकरण के दूसरे घोषित उद्देश्य कालेधन की समाप्ति के संबंध में कुछ समालोचकों का प्रश्न है कि उच्च मूल्य के (500 व 1000 रूपये) के कुल 15 लाख 44 हजार रूपये की राशि के नोटों में से अधिकांश 97 प्रतिशत (14. 97 लाख करोड़) नोट बैकों में जमा हो गये हैं, तो काला धन कहां समाप्त हुआ? लेकिन, देश व विदेश में जमा भारतीयों का कालाधन कोई मात्र 15.14 लाख करोड़ रूपये के बड़े मूल्य के नोटों जितना व केवल इन नोटों में रोकड़ के रूप में ही तो नहीं था अथवा है। विविध विशेषज्ञ अनुमानों के अनुसार भारतवासियों द्वारा जमा कालाधन 100–150 लाख करोड़ रूपये तुल्य रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 60 प्रतिशत के कर व शास्ति के साथ विदेशों में जमा कालेधन व 2016 में 45 प्रतिशत के कर व शस्ति के साथ देश में जमा कालेधन की घोषणा हेतु लायी गई आय घोषणा योजनाओं में क्रमशः 4147 व 65,250 करोड़ रूपये का ही कालाधन सामने आया है। दूसरी ओर अर्जेंटाइना व इंडोनेशिया में अपेक्षाकृत न्यून कर दायित्व के साथ जो आय घोषणा योजनायें लायी गयी थी उनमें भारत की तुलना में कई गुणा अधिक कालेधन की घोषणा की गयी है। अर्जेंटाइना में कुल 80 अरब डालर अर्थात 5,36,000 करोड़ रूपये तुल्य व इंडोनेशिया में योजना के केवल प्रथम चरण में ही 379 अरब डालर अर्थात 25,40,000 करोड़ रूपये तुल्य कालेधन की घोषणा हुयी है। इसमें लगभग 100 अरब डालर अर्थात 6,20,000 करोड़ रूपयों से थोड़ी कम राशि विदेशों में जमा थी। इसमें 70 प्रतिशत सिंगापुर के बैंकों में थी। भारत की अर्थव्यवस्था इण्डोनेशिया की अर्थव्यवस्था से साढ़े तीन गुनी बड़ी है। इसलिये कालेधन की मात्रा भी उसी या और अधिक अनुपात में हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। इसलिये कालाधन मात्र 15.44 लाख करोड़ रूपये के रोकड़ धन में होने की कल्पना उचित नहीं है। कर चोरी अथवा अवैध कारोबार से संचित या भ्रष्टाचार की आय का कालाधन जिन लोगों के पास भी है, वे भूमि, भवन, सोना, शेयर, पार्टिसिपेटरी नोट्स, बेनामी संपत्तियों या अन्य भी किसी रूप में रखते हैं। भ्रष्टाचार की आय से अर्जित धन को या अन्य भी कालेधन को कहीं कारोबार में बताकर निर्यात आय के रूप में सफेद करने के भी कई तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं।

देश में जमा कालेधन की घोषणा हेतु लायी गई आय घोषणा योजनाओं में क्रमशः 4147 व 65,250 करोड़ रू. का ही कालाधन सामने आया है।

लेकिन, एक बात निर्विवादतः सत्य है कि अधिकांश व 90 प्रतिशत से अधिक कालेधन का सृजन रोकड़ लेन–देने से ही संभव है। अतएवं बड़े नोटों की बंदी के साथ अब रोकड़ में लेन–देन व व्यवहार में कमी से देश में कालेधन का निर्माण बाधित होगा। चेक, कार्ड, मोबाइल बैंकिग या इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से होने वाले भुगतान में कर चोरी या बिना हिसाब का भुगतान असंभव है। ऐसे में अल्प रोकड़ अर्थात लैस केश वाली व्यवस्था में कालेधन व अवैध धन पर पर्याप्त अंकुश रहने की सर्वाधिक संभावना रहती है। कहीं न कहीं ऐसे लेन–देन के पदचिन्ह पकड़ में आ ही जाते हैं।

भू–संपदा अर्थात भूखंड, मकानों व अपार्टमेंट आदि में क्रय–विक्रय में सर्वाधिक कालेधन का सृजन होता था। अधिकतम पंजीयन संपति के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य के आधे से कम राशि के होते थे। अब रोकड़ में भुगतान असंभव होने से भू–संपदा व्यवहारों में कमी आयेगी। इससे देश में निर्माण कार्यों में भी कमी आयी है। उसके कारण बजरी भरने वाले श्रमिक से लेकर सभी प्रकार के निर्माण श्रमिकों, कारीगर, प्लंबर, वायरमैन, पेंटर, फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों, सेंटरिंग–शटरिंग कर्ताओं सहित कई श्रेणी के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, लोहा (सरियों), तार–स्विच सहित फिटिंग में प्रयुक्त विद्युत साज–सामानों सेनीटरी सामग्री, व उपकरणों आदि की मांग व उत्पादन में भी कटौती और तत्संबंधी रोजगार में भी कमी आयी है, जो अभी कुछ समय और जारी रहेगी। नवंबर व दिसंबर में दूसरे व तीसरे दर्जे के नगरों में फुटकर कारोबार में 25 प्रतिशत की गिरावट के भी समाचार हैं। ऐसे में उत्पादकों द्वारा मांग में कमी को देखते हुये 2017 की पहली या दूसरी तिमाही में उत्पादन में कटौती व कार्मिकों की छंटनी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र भी रोकड़ लेन–देन पर अधिक आधारित है। इससे संगठित क्षेत्र के कारोबार व असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर

अल्प–रोकड़ (लेस कैश) व्यवस्था में कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। देश में 93 प्रतिशत रोजागार असंगठित क्षेत्र में है।

वस्तुतः आर्थिक गतिविधियाँ मुद्रा की मात्रा पर नहीं मुद्रा हस्तांतरण की गति पर निर्भर करती है। यदि 100 रूपये के एक नोट से कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट से खाना क्रय करता है तो वह रेस्टोरेंट वाला उसके रेस्टोरेंट हेतु सब्जी, तेल, मिर्च, आटा, ब्रेड आदि खरीदेगा और वह सौ रूपये का नोट उपरोक्त सामानों के किसी विक्रेता तक जायेगा। वह विक्रेता आपूर्त्तिकर्त्ता से कोई माल अथवा अपने घरेलू उपभोग हेतु कुछ क्रय करेगा तो वह 100 रूपये का नोट उस आपूत्तिकर्त्ता को जायेगा। इस प्रकार यदि तीन दिन में वह नोट 20 लोगों के बीच घूमेगा तो उस शहर में उस 100 रूपये के एक नोट से 2000 का कारोबार होगा। यदि वह नोट दस लोगों में घूमेगा तो 1000 रूपये का और तीन पक्षकारों में भी उस नोट का अंतरण होगा तो मात्र 300 रूपये का कारोबार ही होगा। इसलिये अल्प रोकड़ का कुछ प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के कुल कारोबार व उसकी मूल्य श्रृंखला पर होना ही है।

यह भी संभव है कि नोटबंदी के बाद, जिन कई लोगों ने अपने पास बड़ी संख्या में रखे बड़े नोटों को बैंक में जमा कराने के लिये 1 अप्रैल से 8 नवंबर 2016 के बीच बढ़ी हुयी कृत्रिम बिक्री बताकर जो रोकड़ पोते (केश इन हैंड) बताने का प्रयास किया है, उससे कागजों में कुल कारोबार भी बढ़ा हुआ आये। ऐसा भी संभव है कि बैंकों में जमा हुये 14.97 खरब रूपये के बड़े नोटों में 5–6 खरब रूपये ऐसी कृत्रिम बिक्री के रास्ते जमा किये गए हों। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2016–17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 1–1.5 प्रतिशत की ऐसी वृद्धि का भी योगदान होगा।

वैसे विगत 21 माह से निर्यातों में कमी, 4 वर्षों से नये निवेश में पूर्ण गतिरोध, बैंकों में बढ़ती अनिष्पादनीय आस्तियां (नान–परफार्मिंग एसेट्स), रूग्ण होते एस्सार जैसे 1.5–2 खरब रूपये मूल्य के उपक्रमों का विदेशी कंपनियों द्वारा किये गए अधिग्रहण आदि से चेतावनी लेते हुये देश में निवेश, उत्पादन व रोजगार संवर्द्धन के द्रुत प्रयास अविलंब आवश्यक हैं। इस सत्य को भी हमें स्वीकारना होगा कि आज वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन (वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरिंग) में भारत का अंश मात्र 2.1 प्रतिशत है जबकि चीन का 22 प्रतिशत है। हमारे इस 2.1 प्रतिशत अंश में भी 2/3 से अधिक विदेशी कंपनियों का है, जो सस्ते श्रम का लाभ उठाने हेतु अपनी कुछ गतिविधियां भारत में संपन्न करा रही हैं या देश में अपने उत्पाद बेचने हेतु बाहर से हिस्से पुर्जे लाकर उन्हें एसेंबल कर रही हैं। ऐसे ही कुछ उत्पाद निर्यात हेतु भी वे यहां एसेंबल कर लेती है। अन्यथा स्वदेशी स्वामित्व युक्त भारतीय उपक्रमों का उत्पादन वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन (वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग) में 0.5–0.6 प्रतिशत रह जाता है। चीन ने वैश्विक विनिर्माणी उत्पादन के लगभग एक चौथाई (22 प्रतिशत) पर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु अपने घरेलू उद्योगों को अत्यंत उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है। चीन ने घरेलू कंपनियों को इतने उदार ऋणों की सुविधा दी थी जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता और पुनः मंदी से उबारने हेतु जो ऋणों का समता पूंजी में परिवर्तन का निर्णय लिया उसकी तो स्वप्न में भी कल्पना कठिन है। उदार व सुगम ऋणों के कारण चीन में कंपनी ऋण (Corporate debt) अक्टूबर 2016 में 180 खरब डालर (12060 खरब रू. तुल्य) हो गया था, जो चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 170 प्रतिशत व भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8 गुणे से भी अधिक था।

नोटबंदी के बाद बढ़ी जमा राशि के बाद रेपो रेट में 0.25-0.50 प्रतिशत कमी बेमानी है।

भारत में सख्त मौद्रिक नीति व अति उच्च ब्याज दरों के कारण अनेक स्थानीय उद्यम वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में यत्किचित अक्षम से होते हैं। आज जब विश्व में 9 देशों में ऋणात्मक ब्याज दर है और अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 1 प्रतिशत से कम ब्याज दरें है, ऐसे में भारत में 6.25 प्रतिशत की रेपो रेट पर उद्यमियों के लिये ऋण की लागत 11–12 प्रतिशत हो जाती है। हाल में नोटबंदी के बाद बढ़ी जमा राशि के बाद 10.30 की गयी, 0.25–0.50 प्रतिशत कमी बेमानी है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मुद्रा स्फीति नियंत्रण के लिए सख्त मौद्रिक नीति व ऊंची ब्याज दरों से कोई लाभ नहीं है। भारत में मुद्रा स्फीति का एक कारण अत्यधिक विदेशी संस्थागत निवेश है, जो वस्तु बाजार में उछाल लाते हैं। दूसरा कारण रूपये की विनिमय दर में निरंतर गिरावट, यथा 2011 के 50 रू. प्रति डालर से गिरकर रूपये की विनिमय दर आज 68 रू. प्रति डालर हो जाने से उत्पादन में प्रयुक्त सभी वस्तुएं 35 प्रतिशत महंगी हो गयी है। तीसरा कारण दलहन आदि की अपर्याप्त आपूर्ति है। इसलिए रेपो रेट को काफी कम किया जाना परम आवश्यक है। देश में औद्योगिक, वाणिज्यि व कृषि क्रियाओं में अवलंब रोजगार–सृजनकारी निवेश में भारी वृद्धि करनी आवश्यक है। इस हेतु भारत को उदार मौद्रिक नीति व ब्याज दरों में

भारी कटौती की ओर बढ़ना होगा। लेकिन, साथ ही व्यापार घाटे वे विनिमय दरों में गिरावट रोकने के लिए आयात प्रतिस्थापक उत्पादों के उत्पादन पर सर्वाधिक बल देने के साथ–साथ सघन कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा। देश में 67 प्रतिशत छोटी कृषि जोतों को देखते हुए सघन कृषि विकास के बिना किसान को आय सुरक्षा सुलभ कराना कठिन है। इस हेतु सिंचाई में प्रचुर सार्वजनिक निवेश, सूखा रोधी प्रजातियों का प्रसार, उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का विकास, जैविक कृषि पर प्रशिक्षण, किसान की आय वृद्धि हेतु समपार्श्विक आर्थिक गतिविधियों के विकास आदि में प्रचुर निवेश आवश्यक है। ऐसे सभी व्यय ग्रीन बॉक्स में होने से विश्व व्यापार संगठन की अनुदान सीमा में भी नहीं आते हैं।

उद्योगों में आज इलेक्ट्रानिक उत्पादों से लेकर सोलर पैनल पर्यंत व दलहनों व तिलहनों से लेकर जलयान निर्माण पर्यंत सभी क्षेत्रों में उदारतापूर्वक निवेश का प्रवाह बढ़ाना होगा। इसके साथ ही रोजगार सघनता पर लघु व सूक्ष्म उद्यगों में भी सार्थक निवेश वृद्धि आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों की समस्याओं के मूल में जाकर विचार करना होगा। उदाहरणतः आज 80 प्रतिशत तक सोलर पैनल चीन से आते हैं। इस उदीयमान उद्योग (सनराइज सेक्टर) के विकास हेतु सिलिकान इनगॉट से लेकर वेफरिंग तक में स्वावलंबन व देश में उत्पादन क्षमता विकास हेतु यदि किसी शासकी अभिकृति या स्पेशल परपज वेहीकल के माध्यम से 50 प्रतिशत तक इक्विटी पार्टनरशिप भी करनी पड़े, तब ऐसा करना अनुचित नहीं होगा। चीन में निगम ऋणों के आवंटन परिमाण को देखते हुए भारत द्वारा भी ऐसे गैर–पारंपरिक उपायों का उपयोग अवांछित नहीं है। आज की वैश्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत वैश्विक स्पर्द्धा के चलते रोजगार सृजक व संधारक उत्पादन व वाणिज्यिक एवं कृषि संबंधी गतिविधियों व कृषि को संधारित करने व उनमें द्रुत विकास हेतु विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का उल्लंघन किये बिना समुचित राजकोषीय व संस्थागत सहयोग अनिवार्य हो गया है। सभी औद्योगिक देश अपने उद्योग व कृषि को अद्यतन बनाये रखने हेतु कन्सोर्टियम रीति से उद्योग सहायता संघों को उदारपूर्वक सहयोग देते हैं। अमरीका, जापान, द.कोरिया, चीन आदि में अत्याधिक ऐसे उद्योग सहायता संघ सक्रिय है, जिनमें उन्नत अनुसंधानों के लिए 60–90 प्रतिशत तक सहयोग राजकोष से किया जा रहा है। भारत में भी आज 400 उद्योग संकुल है, वहां उद्योग सहायता संघों का विकास कर उनमें रोजगार सृजक उत्पादन व निवेश को प्रोत्साहन आवश्यक है। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

View publication stats